रूस द्वारा संयुक्त उद्यम के लिए ऋणों का उपयोग

1841. **श्री सोमपाल :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच सम्पन्न हुए समझौतों के अन्तर्गत रूस अपने ऋणों का उपयोग संयुक्त उद्यमों के वित्त-पोषण के लिए कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) भारत के आर्थिक-हितों की रक्षा करने हेतु इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत तथा रूस के बीच ऐसा कोई निश्चित करार नहीं हुआ है जिसके अनुसार रूस संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए भारत के रुपया ऋण पुनर्भुगतान का उपयोग कर सके।

प्रधान मंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा के दौरान रूसी सरकार ने हमारे रूपया ऋण पुनर्भुगतान का संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रयोग करने में अपनी रूचि जाहिर की थी। चूंकि रूस को भारत के रूपया ऋण का जो पुनर्भुगतान करना है उसका उपयोग इस समय रूस को भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए संगत अन्तः सरकारी करारों तथा विभिन्न तकनीकी मुद्दों के संकल्प में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही विस्तृत रूपात्मकताओं पर सहमति ही हुई है।

कॉफी का कम उत्पादन

1842. **श्री सोमपाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान काफी का उत्पादन भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के अन्य देशों में भी आवश्यकता से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके पिछले वर्ष के क्या आंकड़े हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि काफी का अधिक मात्रा में निर्यात किये जाने तथा इसका कम उत्पादन होने के कारण इसके मूल्यों में आशातित वृद्धि हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान काफी की विभिन्न किस्मों के मूल्यों की सापेक्ष स्थिति क्या रही है ; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने, विशेष रूप से काफी के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत में काफी का 1,80,000 मी० टन का अनुमानित उत्पादन अनुमानित घरेलू आवश्यकता से कम नहीं है। किन्तु, अन्य देशों के इसी तरह के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान भारत में काफी का अनुमानित उत्पादन लगभग 2,04,000 मी० टन था जो 60.60 कि० ग्रा० के 3.4 मिलियन बोरों के बराबर था जिनमें से जबकि पिछले वर्ष के दौरान विश्व का अनुमानित उत्पादन 60.60 किग्रा0 के 94.2 मिलियन बोरों का था।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न कारणों से हाल में काफी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें से एक कारण ब्राजील की फसल को हुई कथित हानि का भी है। परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन (आई सी ओ) संकेतक कीमत, जिसे

भारत में नीलामियों के लिये आरक्षित कीमत के रूप में लिय जाता है, घरेलू बाजार में ऊंची कीमत परिलक्षित होती रही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों की काफी की सापेक्षिक कीमत की स्थिति निम्नलिखित है:

(औसत कीमत प्रति 50 किग्रा–रूपये में)

वर्ष	प्लांट "ए"
1991	1926.50
1992	1698.48
1993	2185.55

अरेब. चाई		रोब. चाई	
क	ख	क	ख
1594.75		1467.25	
1545.31		1308.33	
1806.35		1658.70	

(ङ) काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) गहन कृषि स्वरूप को अपनाना;

(2) पुराने तथा मृतप्राय काफी बागानों में नई तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों का पुनर्रोपण करना;

(3) सिचाई व्यवस्थाओं में कारगर सुधार;

(4) काफी बेरी-बोरर पेस्ट तथा अन्य बीमारियों का जैविकीय नियंत्रण ।

निर्यात को बढ़ाने के लिये काफी विपणन को पिछले 50 वर्षों में पहली बार उदार बनाया गया है । ऐसा मुक्त बिक्री कोटा की शुरूआत करके किया गया है जिसके तहत उपजकर्ता अपनी उपज का 50% घरेलू और विदेशी बाजारों में बेच सकता है । काफी बोर्ड भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में प्रचार अभियान भी चलाता है ।

भारत-नेपाल व्यापार समझौता

1843. **श्री सोमपाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1994 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में कुछ लोगों द्वारा भारत-नेपाल व्यापार समझौते का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । इकोनोमिक टाइम्स के दिनांक 22 जून, 1994 के दिल्ली तथा कलकत्ता संस्करण प्राप्त हुये हैं उनमें भारत नेपाल व्यापार करार के बारे में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Ratification of GATT by Parliament

1844. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the GATT Agreement is likely to be brought for the approval during the Monsoon Session of the Parliament and whether Government have carefully examined the interests of farmers in the country in the light of GATT agreement on fertilizer subsidy and price structure of fertilizers/pesticides; and

(b) if so, whether Government propose to take all other Political parties/Groups